

Daily Current Affairs

28 July 2025

All Government

**ONE DAY
EXAMS!**



BANK



RAILWAY



SSC



TEACHING



STATE
EXAMS



Expert Live
Classes



Comprehensive
Study Material



Mock Tests &
PYQs



Performance
Tracking



25,000+ PDF
Study Material


Adda247
INDIA'S NO.1 GOVT JOB PREP APP



25,000+

FREE PYP PDFs

OR ATTEMPT AS



MOCK TESTS

START PRACTICING NOW! →

Daily Current Affairs Quiz 28 July 2026

Q1. बिहार सरकार और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) ने बिहार में किस स्थान पर महिलाओं के लिए एक स्थायी राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान (NSTI-W) परिसर की स्थापना की घोषणा की?

- (a) गया
- (b) मुजफ्फरपुर
- (c) बिहटा
- (d) भागलपुर

Ans.(c)

Sol. सही उत्तर है: (c)

व्याख्या:

- जुलाई 2026 में, बिहार सरकार और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) ने बिहटा, बिहार में महिलाओं के लिए एक स्थायी राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान (NSTI-W) परिसर की स्थापना की घोषणा की।
- महिलाओं के लिए आधुनिक बुनियादी ढांचा और उद्योग-अनुकूल कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए ₹99.97 करोड़ के निवेश से परिसर विकसित किया जाएगा।
- परिसर के साथ, वैश्विक रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए ₹7 करोड़ के निवेश के साथ बिहार में एक स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर (SIIC) भी स्थापित किया जाएगा।

Information Booster:

- इस पहल की घोषणा बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और MSDE के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जयंत चौधरी ने की।
- प्रशिक्षण महानिदेशालय (DGT) के महानिदेशक दिलीप कुमार द्वारा आधारशिला रखी गई।
- स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर (SIIC) भाषा प्रशिक्षण, अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन, और सुरक्षित प्रवासन सहायता प्रदान करेगा।
- इस पहल का उद्देश्य महिला कौशल विकास, युवा रोजगार, और अंतर्राष्ट्रीय कार्यबल गतिशीलता को मजबूत करना है।

Additional Knowledge:

- NSTI-W, पटना महिलाओं के लिए बिहार का एकमात्र केंद्र सरकार का कौशल प्रशिक्षण संस्थान है।
- यह क्राफ्ट्समेन ट्रेनिंग स्कीम (CTS) और क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम (CITS) के तहत प्रशिक्षण प्रदान करता है।
- कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) स्किल इंडिया मिशन के तहत पूरे भारत में कौशल विकास पहलों के समन्वय के लिए जिम्मेदार है।

Q2. भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (ZSI) के वैज्ञानिकों ने जुलाई 2026 में किस भारतीय राज्य से मकड़ी की नई प्रजाति *Simonia lawbah* की खोज की?

- (a) अरुणाचल प्रदेश
- (b) मेघालय
- (c) आंध्र प्रदेश
- (d) केरल

Ans.(b)

Sol. सही उत्तर है: (b)

व्याख्या:

- जुलाई 2026 में, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (ZSI) के वैज्ञानिकों ने मेघालय की क्रेम लॉबाह गुफा से गुफा में रहने वाली रे स्पाइडर (cave-dwelling ray spider) की एक नई प्रजाति, *Simonia lawbah* की खोज की।
- यह Theridiosomatidae परिवार से संबंधित है और भारत में सिमोनिया (*Simonia*) वंश के पहले रिकॉर्ड का प्रतिनिधित्व करती है।
- यह प्रजाति आकार में 2 mm से कम है, ट्रोग्लोफिलिक (troglophilic) है (गुफा के आवासों के अनुकूल), और उड़ने वाले कीड़ों को पकड़ने के लिए शंक्राकार रे वेब (cone-shaped ray web) बनाती है।

Information Booster:

- ZSI ने पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, आंध्र प्रदेश से लिंक्स स्पाइडर (lynx spider) की एक नई प्रजाति, *Hamataliwa papikonda* की भी खोज की।
- *Hamataliwa papikonda* Oxyopidae परिवार से संबंधित है।
- यह आंध्र प्रदेश में हैमेटालिवा (*Hamataliwa*) वंश का पहला रिकॉर्ड है।
- ये खोजें सहकर्मि-समीक्षित पत्रिकाओं (peer-reviewed journals) Zootaxa और Records of the Zoological Survey of India में प्रकाशित हुई थीं।

Additional Knowledge:

- भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (ZSI) की स्थापना 1916 में हुई थी।
- इसका मुख्यालय कोलकाता, पश्चिम बंगाल में है।
- ZSI पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) के तहत कार्य करता है।
- हैमेटालिवा (*Hamataliwa*) वंश में दुनिया भर में लगभग 90 प्रजातियां शामिल हैं, जिनमें से 10 प्रजातियां भारत में दर्ज की गई हैं।

Q3. जुलाई 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा ₹3,030 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ स्वीकृत भव्य-रसायन (BHAVYA-Rasayan) योजना का उद्देश्य क्या है:

- (a) भारत में तीन सेमीकंडक्टर निर्माण केंद्र स्थापित करना
- (b) भारत में तीन समर्पित बड़े रासायनिक पार्क स्थापित करना
- (c) पूरे भारत में तीन एकीकृत टेक्सटाइल पार्क विकसित करना
- (d) भारत में तीन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन क्षेत्र बनाना

Ans.(b)

Sol. सही उत्तर है: (b)

व्याख्या:

- जुलाई 2026 में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत औद्योगिक विकास योजना रसायन (भव्य-रसायन) योजना को मंजूरी दी।
- इस योजना का उद्देश्य भारत के रासायनिक निर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करने के लिए तीन समर्पित बड़े रासायनिक पार्क स्थापित करना है।
- इसका कुल वित्तीय परिव्यय ₹3,030 करोड़ है और इसे पांच वर्षों (वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2030-31) में लागू किया जाएगा।

Information Booster:

- इस योजना की घोषणा सबसे पहले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा केंद्रीय बजट 2026-27 में की गई थी।
- कुल ₹3,030 करोड़ में से, ₹3,000 करोड़ सामान्य बुनियादी ढांचे और बुनियादी उपयोगिताओं के लिए निर्धारित हैं, जबकि ₹30 करोड़ प्रशासनिक खर्चों के लिए आवंटित किए गए हैं।
- रासायनिक पार्कों का विकास राज्य सरकारों द्वारा एक चुनौती-आधारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा।
- प्रत्येक पार्क में कम से कम 2,000 एकड़ (8 वर्ग किमी) निकटवर्ती, बाधा-मुक्त भूमि होनी चाहिए।

Additional Knowledge:

- भव्य-रसायन योजना के साथ, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी-गुंतकल खंड पर तीसरी और चौथी रेलवे लाइनों को मंजूरी दी।
- रेल परियोजना की अनुमानित लागत लगभग ₹1,264 करोड़ है और इसे 2028-29 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
- यह परियोजना भारतीय रेलवे नेटवर्क का लगभग 46 किमी विस्तार करेगी।
- इससे लगभग 7 लाख की कुल जनसंख्या वाले लगभग 99 गांवों के लिए कनेक्टिविटी में सुधार होने की उम्मीद है।

Q4. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद – केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान (ICAR-CMFRI) ने जुलाई 2026 में किस मिशन के तहत 'DeepDATA' मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च किया?

(a) राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास मिशन

(b) डीप ओशन मिशन

(c) नीली क्रांति मिशन

(d) सागरमाला कार्यक्रम

Ans.(b)

Sol. सही उत्तर है: (b)

व्याख्या:

• जुलाई 2026 में, ICAR-CMFRI ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) के डीप ओशन मिशन के तहत कोच्चि, केरल में DeepDATA मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च किया।

• यह ऐप गहरे समुद्र की मछली प्रजातियों पर वैज्ञानिक रूप से सत्यापित जानकारी प्रदान करता है, जिसमें उनका वर्गीकी (वर्गीकरण), विशेषताएं, वितरण और संरक्षण स्थिति शामिल हैं।

• यह शोधकर्ताओं, मछुआरों और नागरिकों को क्षेत्रीय अवलोकन अपलोड करने में भी सक्षम बनाता है, जिन्हें एक राष्ट्रीय डिजिटल रिपोजिटरी में जोड़े जाने से पहले ICAR-CMFRI विशेषज्ञों द्वारा सत्यापित किया जाता है।

Information Booster:

• DeepDATA गहरे समुद्र की खोज, समुद्री जैव विविधता अनुसंधान, और समुद्री संसाधन मूल्यांकन का समर्थन करता है।

• यह ऐप गहरे समुद्र की मछली प्रजातियों के दस्तावेजीकरण में सार्वजनिक भागीदारी की अनुमति देकर नागरिक विज्ञान (सिटीजन साइंस) को बढ़ावा देता है।

• सत्यापित सबमिशन गहरे समुद्र की जैव विविधता के एक राष्ट्रीय डिजिटल रिपोजिटरी में योगदान करते हैं।

• इस लॉन्च में डॉ. ग्रिनसन जॉर्ज (निदेशक, ICAR-CMFRI), डॉ. एल्डहो वर्गीज, और डॉ. रेखा जे. नायर शामिल हुए।

Additional Knowledge:

• ICAR-CMFRI (केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के तहत एक प्रमुख समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान है।

• इसका मुख्यालय कोच्चि, केरल में है।

• पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) द्वारा शुरू किए गए डीप ओशन मिशन का उद्देश्य उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से भारत के गहरे महासागरीय संसाधनों का पता लगाना और उनका सतत उपयोग करना है।

Q5. संयुक्त राष्ट्र प्रत्येक वर्ष किस तिथि को न्यायिक कल्याण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस (International Day for Judicial Well-being) मनाता है?

(a) 21 जून

(b) 25 जुलाई

(c) 4 मार्च

(d) 10 दिसंबर

Ans.(b)

Sol. सही उत्तर है: (b)

व्याख्या:

• न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों के मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक कल्याण पर जोर देने के लिए प्रतिवर्ष 25 जुलाई को न्यायिक कल्याण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस (International Day for Judicial Well-being) मनाया जाता है।

• यह स्वीकार करता है कि न्यायिक कल्याण न्यायिक अखंडता, कानून के शासन और न्याय के प्रभावी वितरण के लिए आवश्यक है।

• यह दिन 25 जुलाई 2024 को न्यायिक कल्याण पर नौरू घोषणा (Nauru Declaration on Judicial Well-being) को अपनाते के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जो न्यायिक कल्याण को समर्पित पहला अंतर्राष्ट्रीय घोषणापत्र है।

Information Booster:

- संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने प्रस्ताव A/RES/79/266 के माध्यम से इस दिवस को मनाने की घोषणा की।
- यह प्रस्ताव 58वीं प्लेनरी बैठक के दौरान 4 मार्च 2025 को अपनाया गया था।
- न्यायिक कल्याण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का पहला आयोजन 25 जुलाई 2025 को किया गया था।
- नौरू घोषणा दुनिया भर में न्यायिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सात मार्गदर्शक सिद्धांतों की रूपरेखा तैयार करती है।

Additional Knowledge:

- न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निष्पक्षता और दक्षता सुनिश्चित करने में न्यायिक कल्याण को एक प्रमुख कारक के रूप में तेजी से पहचाना जा रहा है।
- यह आयोजन दुनिया भर की न्यायपालिकाओं को ऐसे उपाय अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है जो न्यायाधीशों के मानसिक स्वास्थ्य और लचीलेपन का समर्थन करते हैं।
- संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) संयुक्त राष्ट्र का मुख्य नीति-निर्माण अंग है, जिसमें सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्य देश शामिल हैं।

Q6. जुलाई 2026 में आयोजित प्रौद्योगिकी हस्तांतरण कार्यक्रम के दौरान, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) ने ग्रामीण जल प्रबंधन के लिए किस IoT-सक्षम प्रणाली को व्यावसायिक रूप से लॉन्च किया?

- (a) स्मार्ट अर्बन वॉटर ग्रिड सिस्टम
- (b) स्मार्ट रूरल वॉटर सर्विस डिलीवरी, मेजरमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम
- (c) नेशनल वॉटर क्वालिटी सर्विलांस सिस्टम
- (d) डिजिटल जल शक्ति मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म

Ans.(b)

Sol. सही उत्तर है: (b)

व्याख्या:

- जुलाई 2026 में, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) ने CSIR मुख्यालय, नई दिल्ली में आयोजित प्रौद्योगिकी हस्तांतरण कार्यक्रम के दौरान व्यावसायिक रूप से एक IoT-सक्षम स्मार्ट रूरल वॉटर सर्विस डिलीवरी, मेजरमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किया।
- इस कार्यक्रम का आयोजन CSIR-केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन (CSIR-CSIO), चंडीगढ़ द्वारा किया गया था।
- CSIR ने पंप अकादमी प्राइवेट लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) को चार स्वदेशी प्रौद्योगिकियों का हस्तांतरण भी किया।

Information Booster:

- इस कार्यक्रम की अध्यक्षता CSIR की महानिदेशक और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग (DSIR) की सचिव डॉ. एन. कलैसेल्वी ने की।
- पंप अकादमी प्राइवेट लिमिटेड को हस्तांतरित चार प्रौद्योगिकियां हैं:
- इंडक्शन मोटर स्टेथोस्कोप (MSCOPE)
- पोर्टेबल एंड यूनिवर्सल मोटर-कम-पंप परफॉर्मेंस मॉनिटर (PU-MPPM)
- i-पावर क्वालिटी एनालाइजर (IPQA)
- स्मार्ट रूरल वॉटर सर्विस डिलीवरी, मेजरमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम
- भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) को स्वदेशी रक्षा प्रणालियों के लिए प्रौद्योगिकी लाइसेंस प्राप्त हुए।

Additional Knowledge:

- BEL ने स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकियों के लाइसेंस प्राप्त उत्पादन के लिए CSIR-CSIO को रॉयल्टी के रूप में ₹1.67 करोड़ का भुगतान किया।
- इन प्रौद्योगिकियों में हेड-अप डिस्प्ले (HUD), ड्रोग लाइट्स, टैक्सी लैंडिंग लाइट्स, HUD लेवल-I टेस्टर, बोरसाइट अलाइनमेंट टूल, और HUD के लिए ऑप्टिकल मॉड्यूल एंड बीम कंबाइनर असेंबली शामिल हैं।
- CSIR भारत का प्रमुख सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित अनुसंधान और विकास संगठन है जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत काम करता है।

Q7. इलेक्ट्रिक मर्चेन्ट्स एसोसिएशन (EMA) के अध्यक्ष प्रेम के. वोरा को जुलाई 2026 में नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय नेतृत्व सम्मेलन में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया?

- (a) पद्म श्री
- (b) राष्ट्रीय अशोक सम्मान (भारत सम्मान)
- (c) राष्ट्रीय एमएसएमई उत्कृष्ट पुरस्कार
- (d) उद्योग रत्न पुरस्कार

Ans.(b)

Sol. सही उत्तर है: (b)

व्याख्या:

- जुलाई 2026 में, 2025-26 के लिए इलेक्ट्रिक मर्चेन्ट्स एसोसिएशन (EMA) के अध्यक्ष प्रेम के. वोरा को नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय नेतृत्व सम्मेलन में राष्ट्रीय अशोक सम्मान (भारत सम्मान) से सम्मानित किया गया।
- उन्हें भारत के विद्युत व्यापार क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान, नैतिक व्यावसायिक प्रथाओं को बढ़ावा देने और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को मजबूत करने के प्रति उनके समर्पण के लिए यह पुरस्कार मिला।
- उनके नेतृत्व में, EMA ने डिजिटल परिवर्तन, सतत व्यावसायिक प्रथाओं, और विद्युत व्यापार के मजबूत प्रतिनिधित्व पर जोर दिया है।

Information Booster:

- प्रेम के. वोरा इलेक्ट्रिक मर्चेन्ट्स एसोसिएशन (EMA) के सबसे युवा अध्यक्ष हैं।
- उन्होंने सतत व्यावसायिक प्रथाओं को प्रोत्साहित करने के लिए "ग्रीन इलेक्ट्रिकल्स" पहल को बढ़ावा दिया।
- उन्हें ग्लोबल यूथ एंबेसडर अवॉर्ड (2025 और 2026) से भी सम्मानित किया जा चुका है।
- उन्हें इलेक्ट्रिकल उद्योग 2025 में आइकॉनिक इमर्जिंग लीडर के रूप में मान्यता दी गई थी।

Additional Knowledge:

- इलेक्ट्रिक मर्चेन्ट्स एसोसिएशन (EMA) की स्थापना 1937 में हुई थी।
- यह एक गैर-लाभकारी संगठन है जो भारत के विद्युत उद्योग और व्यापार के हितों की रक्षा और संवर्धन के लिए समर्पित है।
- EMA का मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है।
- यह संघ विद्युत क्षेत्र में नवाचार, नीति वकालत और सतत विकास का समर्थन करने के लिए काम करता है।

Q8. हेनले पासपोर्ट इंडेक्स (HPI) - जुलाई 2026 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

1. भारत 55 गंतव्यों के लिए वीजा-मुक्त या ऑन-अराइवल वीजा पहुंच के साथ विश्व स्तर पर 81वें स्थान पर रहा।
2. सिंगापुर ने पूर्व वीजा के बिना 192 गंतव्यों तक पहुंच के साथ शीर्ष स्थान बरकरार रखा।
3. जापान, दक्षिण कोरिया और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने संयुक्त रूप से 188 गंतव्यों तक पहुंच के साथ दूसरा स्थान हासिल किया।
4. अफगानिस्तान केवल 22 गंतव्यों तक पहुंच के साथ सूचकांक में अंतिम स्थान पर रहा।

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1, 3 और 4
- (d) 1, 2, 3 और 4

Ans.(d)

Sol. उत्तर

- (d) 1, 2, 3 और 4

व्याख्या

- कथन 1 सही है क्योंकि भारत हेनले पासपोर्ट इंडेक्स – जुलाई 2026 में 55 गंतव्यों तक पहुंच के साथ 81वें स्थान पर रहा, जो फरवरी 2026 संस्करण के 75वें स्थान से नीचे है।
- कथन 2 सही है क्योंकि सिंगापुर ने 192 गंतव्यों के लिए वीजा-मुक्त पहुंच प्रदान करते हुए दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट का दर्जा बरकरार रखा।
- कथन 3 सही है क्योंकि जापान, दक्षिण कोरिया और संयुक्त अरब अमीरात संयुक्त रूप से 188 गंतव्यों तक पहुंच के साथ दूसरे स्थान पर रहे।
- कथन 4 सही है क्योंकि अफगानिस्तान केवल 22 गंतव्यों तक पहुंच के साथ सूचकांक में सबसे नीचे बना रहा।

Information Booster

हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में टॉप 3 – जुलाई 2026

रैंक	देश	वीजा-मुक्त पहुँच (Visa-free Access)
1	सिंगापुर	192 गंतव्य
2	जापान, दक्षिण कोरिया, संयुक्त अरब अमीरात	188 गंतव्य
3	स्वीडन	187 गंतव्य

भारत का प्रदर्शन

- रैंक: 81वाँ
- वीजा-मुक्त/वीजा-ऑन-अराइवल/eTA पहुँच: 55 गंतव्य
- पिछली रैंक (फरवरी 2026): 75वाँ

Additional Knowledge

- हेनले पासपोर्ट इंडेक्स हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा प्रकाशित किया जाता है।
- यह सूचकांक इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा प्रदान किए गए डेटा पर आधारित है।
- यह 227 यात्रा गंतव्यों में 199 पासपोर्टों का मूल्यांकन करता है और निम्नलिखित पर विचार करता है:

- वीजा-मुक्त पहुँच
- वीजा-ऑन-अराइवल पहुँच
- इलेक्ट्रॉनिक ट्रेवल ऑथराइजेशन (eTA)

सबसे निचले पाँच देश

- अफगानिस्तान – 22 गंतव्य
- सीरिया – 25 गंतव्य
- इराक – 28 गंतव्य
- पाकिस्तान – 29 गंतव्य
- यमन – 30 गंतव्य

Q9. अर्काडी ड्वोरकोविच द्वारा स्वेच्छा से अपने कर्तव्यों को निलंबित करने के बाद जुलाई 2026 में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ (FIDE) के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला?

- मैग्नस कार्लसन
- विश्वनाथन आनंद
- ब्लादिमीर क्रैमनिक
- गैरी कास्पारोव

Ans.(b)

Sol. सही उत्तर है: (b)

व्याख्या:

- जुलाई 2026 में, भारत के पांच बार के विश्व शतरंज चैंपियन और FIDE के उपाध्यक्ष विश्वनाथन आनंद ने अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ (FIDE) के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला।
- उन्होंने यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध को लेकर यूरोपीय संघ (EU) और स्विट्जरलैंड द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के बाद अर्काडी व्लादिमीरोविच ड्वोरकोविच द्वारा स्वेच्छा से अपने कर्तव्यों को निलंबित करने के बाद यह पदभार संभाला।

Information Booster:

- विश्वनाथन आनंद ने पांच बार विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीती: 2000, 2007, 2008, 2010, और 2012।
- वह कई बार विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले एकमात्र भारतीय हैं।
- अगस्त 2022 में, उन्हें FIDE का उपाध्यक्ष चुना गया था।
- FIDE (अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ) शतरंज खेल का वैश्विक शासी निकाय है।

Additional Knowledge:

- विश्वनाथन आनंद को 1985 में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ।
- उन्हें 1988 में पद्म श्री, 1991-92 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, 2001 में पद्म भूषण, और 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था।
- पद्म विभूषण भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है।
- आनंद को व्यापक रूप से खेल के इतिहास में सबसे महान शतरंज खिलाड़ियों में से एक माना जाता है और उन्होंने भारत में शतरंज को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

Q10. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक विरोधी उपायों को मजबूत करने के लिए जुलाई 2026 में लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 में संशोधनों को मंजूरी दी। प्रस्तावित संशोधनों के तहत, संगठित पेपर लीक अपराधों के लिए अधिकतम जुर्माना क्या है:

- (a) 7 साल का कारावास और ₹1 करोड़ तक का जुर्माना
- (b) 10 साल का कारावास और ₹5 करोड़ तक का जुर्माना
- (c) 10 साल का कारावास और ₹10 करोड़ तक का जुर्माना
- (d) आजीवन कारावास और ₹50 करोड़ तक का जुर्माना

Ans.(c)

Sol. सही जवाब: (c) 10 साल का कारावास और ₹10 करोड़ तक का जुर्माना

व्याख्या:

- जुलाई 2026 में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 में संशोधन के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दी।
- प्रस्तावित संशोधनों का उद्देश्य सख्त सजा शुरू करके संगठित पेपर लीक अपराधों पर अंकुश लगाना है।
- संशोधित प्रावधानों के तहत, अपराधियों को संगठित परीक्षा धोखाधड़ी के लिए 5-10 साल के कारावास और ₹10 करोड़ तक के जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है।
- संशोधनों में पेपर लीक मामलों की त्वरित जांच और निपटान सुनिश्चित करने के लिए फास्ट-ट्रैक अदालतों का भी प्रावधान है।

Information Booster:

- प्रस्तावित संशोधन संगठित पेपर लीक अपराधों के लिए न्यूनतम कारावास को 3 साल से बढ़ाकर 5 साल करते हैं।
- अधिकतम कारावास 10 साल बना हुआ है।
- संगठित अपराधों के लिए अधिकतम जुर्माना बढ़ाकर ₹10 करोड़ कर दिया गया है।
- तीन महीने के भीतर जांच और सुनवाई पूरी करने के लिए समर्पित फास्ट-ट्रैक अदालतों का प्रस्ताव है।

Additional Knowledge:

- केंद्रीय प्राधिकरणों द्वारा आयोजित सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित प्रथाओं को रोकने के लिए लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 लागू किया गया था।
- यह अधिनियम पेपर लीक, प्रश्न पत्रों तक अनधिकृत पहुंच, नकल सिंडिकेट और संगठित परीक्षा धोखाधड़ी जैसे अपराधों को लक्षित करता है।
- संशोधनों का उद्देश्य पूरे भारत में सार्वजनिक भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं की विश्वसनीयता, पारदर्शिता और अखंडता को बढ़ाना है।


Adda247
INDIA'S NO.1 GOVT JOB PREP APP

All Government **ONE DAY EXAMS!**

**BANK****RAILWAY****SSC****TEACHING****STATE EXAMS**

**Expert Live Classes****Comprehensive Study Material**

**Mock Tests & PYQs****Performance Tracking**

**25,000+ PDF Study Material**

**PDF**

25,000+
FREE PYP PDFs
OR ATTEMPT AS
**MOCK TESTS**

START PRACTICING NOW! →